बीमारू के बाद अब डीमारू राज्य

आशीष बोस

2001 के जनगणना आयुक्त ने तुरन्त ही इस दुखद तथ्य को पहचान लिया कि बहुत सारे राज्यों के बाल स्त्री-पुरुष अनुपात में भारी गिरावट आई है। इस तथ्य की व्याख्या आप्रवास के आधार पर नहीं की जा सकती है। यह शायद सीधे-सीधे लड़कियों की हत्या अथवा लड़कियों की अपेक्षाकृत अधिक मृत्यु दर का परिणाम न हो, लेकिन इसमें मादा भ्रूण हत्या का हाथ ज़रूर है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रगतिशील माने जाने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों में भी, केरल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में बाल लिंग अनुपात में कमी आई है।

विश्व में कहीं भी जनगणना सम्पन्न कराना एक अत्यंत कठिन कार्य है। भारत जैसे वृहद जनसंख्या एवं विविधताओं वाले देश में तो यह और भी मुश्किल है। बहुत से पाश्चात्य देशों में जनगणना को निजता (प्राइवेसी) के हनन के आधार पर चुनौती दी गई है। कुछ देशों में इसे महत्वहीन माना जाता है क्योंकि वहां पंजीयन और आप्रवास की सूचना रखने की बेहतर व्यवस्था है। भारत में नियोजन और नीति निर्धारण के लिए जनगणना काफी उपयोगी मानी जाती है। बहुत सारे नमूना सर्वेक्षणों के बावजूद जनगणना लोगों के जीवन के बारे में सूचना देने का एकमात्र महत्वपूर्ण स्त्रोत है।

अंग्रेज़ों ने जनगणना की शुरुआत 1872 में की थी और 1881 से प्रत्येक दसवें साल हमारे यहां जनगणना होती रही है। सन् 2001 की जनगणना इस क्रम की 14वीं और स्वतंत्रता के बाद की 6ठी है। दुनिया के कम ही देशों के पास दस वर्षीय जनगणना को लगातार सम्पन्न कराने का अटूट रिकार्ड है। अंग्रेज़ों ने जनगणना के लिए राजस्व अधिकारियों और विद्यालयों के शिक्षकों का 'स्वैच्छिक' आधार पर उपयोग किया था और इसके लिए उन्हें कोई विशेष भुगतान भी नहीं दिया जाता था।

जनगणना कार्य के पूर्व व दौरान की गई अपनी यात्राओं के क्रम में मैने स्वयं जनगणना कर्मियों में उत्साह की कमी को महसूस किया। जनसंख्यात्मक संवेग, एक शब्द जो तकनीकी जनसंख्या विज्ञान में सम्भावित जनसंख्या वृद्धि पर उम्र-वितरण के प्रभाव को दर्शाता है, के बदले मैं भारत में जनगणना कराने की प्रक्रिया की व्याख्या हेतु जनगणना संवेग जैसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा। प्रत्येक जनगणना आयुक्त प्रश्नावलियों और इसकी वर्गीकरण योजना में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वही करता है जो अब तक होता आया है तथा नौकरशाही, जो प्रकृति से ही लकीर की फकीर होती है, में ज़िला अधिकारी से लेकर जनगणना आयुक्त तक एक श्रंखला बन जाती है और येन-केन-प्रकारेण जनगणना सम्पन्न हो जाती है।

जनगणना कर्मियों के लिए मानदेय स्वरूप थोड़ी सी राशि की व्यवस्था 1961 से शुरू की गई तथा इसमें धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी होती गई। लेकिन यह स्पष्ट होता गया कि ये तथाकथित स्वैच्छिक-जनगणनाकर्मी स्वैच्छिकता से कोसों दूर थे तथा जनगणना के कार्य को अनिच्छापूर्वक करते थे। समय के साथ स्थिति खराब ही होती गई है। इस उपभोगवादी दौर में महज़ राष्ट्रभक्ति की अपील से काम चलने वाला नहीं।

2001 के जनगणना आयुक्त, जे. के. बांठिया को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने जनगणना को सुचारु रूप से सम्पन्न करा लिया और विपत्तियों में फंसे राज्य जम्मू और कश्मीर में भी इसे सम्भव बना दिया। उन्हें एक अन्य गंभीर समस्या से भी जूझना पड़ा क्योंकि सन् 2000 में तीन नए राज्य झारखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तरांचल निर्मित हुए। इस कारण कई प्रशासनिक समस्याएं खड़ी हुईं।

जनगणना 2001 में किस हद तक अल्प-गणना की गई है इस पर तथा इसके आंकड़ों की गुणवत्ता पर टिप्पणी